जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 29 संख्याः 162 प्रभात उदयपुर, शनिवार 16 अप्रेल, 2022 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

वॉरशिप मॉस्कोवा (2013 की तस्वीर), जिसने यूक्रेन के शहरों पर क्रूज़ मिसाइलें दागी थीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेल-गैस भंडारों, सैन्य अड्डों व नागरिक प्रशासन की इमारतों को निशाना बनाया था, अन्ततः यूक्रेन के जवाबी हमले में डूब गया। मॉस्कोवा के डूब जाने को यूक्रेन वॉर का ''टर्निंग पॉइन्ट'' माना जा रहा है। इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध में डूबे जर्मनी के युद्धपोत बिस्मार्क से की जा रही है। जिस तरह बिस्मार्क जर्मनी की नौसेना की ताकत का प्रतीत था वैसे ही मॉस्कोवा भी रुस की नौसेना का ''पावर स्टेटमैंट'' माना जाता था और 12500 टन की क्षमता वाला यह गाइडेड मिसाइल क्रूज़र पहले रुस के सीरियाई अभियान में तैनात किया गया था। एंटी शिप, एंटी एयर क्राफ्ट मिसाइल पैड युक्त मॉस्कोवा में पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम टॉरपीडो भी लगे थे। बताया जाता है, जब जहाज डूबा तो उस पर 510 लोग थे, अभी यह पता नहीं है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं। समुद्र में तैरते दुर्भेद्य किले सरीखे इस जहाज को डुबोकर युक्रेन की सैन्य कार्यवाही क्षमता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। विडम्बना ही है कि यूक्रेन के जवाबी प्रहार में डूबा मॉस्कोवा 1980 के दशक में यूक्रेन में ही बना था। तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि, हमारी औरतों और बच्चों की हत्या करने के लिए यह पुतिन को हमारा छोटा सा जवाब है।

रूस का अति शक्तिशाली ''वॉर शिप'' मॉस्कोवा डूबा यूक्रेन के आक्रमण के बाद

''मॉस्कोवा'' एक तैरते किले के समान था, क्योंकि उस पर एंटी शिप व ''एंटी एयर क्राफ्ट'' मिसाइल लगे हुए थे तथा पनडुब्बी के आक्रमण का सामना करने के लिये ''टारपीडो'' भी थे

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। रूस के ब्लैक सी फ्लोटिला फ्लीट के प्रमुख युद्धपोत का डूबना यूक्रेन युद्ध और विश्वभर के सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

रूस इस बात को नहीं मानता कि युद्धपोत को यूक्रेन की मिसाइलों ने गिराया होगा। उनका मानना है कि जहाज के अन्दर लगी आग ने उसके संरचनात्मक संतुलन को नुकसान पहुंचाया और वह एक तरफ झुककर उफनते समुद्र में समा गया। इस तरह के जहाज के डूबने की तुलना शायद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबे जहाज ''द बिस्मार्क'' से भविष्य में की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध में ''द बिस्मार्क'' को जर्मनी की नौसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता था।

हालांकि जहाज डूबने के बाद रूस ने कीव के आस पास के इलाकों पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। यूक्रेन को आशंका है कि अपने फ्लैगशिप युद्धपोत के डूबने के बाद रूस यूक्रेन में हमले और तेज करेगा।

इसमें कोई संशय नहीं कि जहाज डूबने से रूस और विशेष रूप से व्लादिमीर पुतिन की प्रतिष्ठा पर एक गहरा आघात है। रूसी तानाशाह अब यूक्रेन के ठिकानों पर दोगुने हमले कर अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे।

समुद्र में डूबा जहाज ''मॉस्कोवा'' 12,500 टन गाइडेड मिसाइल्स क्रूजर था और रूस की नौसेना की ताकत था। इस युद्धपोत को इससे पहले रूस के सीरिया अभियान के दौरान तटीय सुरक्षा और जमीन से मिसाइलें दागने की जरूरतों पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया था।

इसके बाद जब टर्की ने रूस के कई लड़ाकू विमान मार गिराए थे तब गुस्साए व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्धपोत को ब्लैक सी में भेजा था जहां उसने एक क्षेत्र में फ्लोटिला फ्लीट के साथ अपनी वास्तविक पहचान बनाई थी और विविध उद्देश्य पूर्ण किए थे।

मॉस्कोवा में पनडुब्बियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले टारपीडोज के अलावा एंटी शिप और एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल्स पैड्स भी लगे थे। इसकी स्पीड 32 मील प्रतिघंटा थीं तथा यह 6 सौ फीट लंबा था। इसी तरह का एक युद्धपोत इससे पहले अर्जेन्टीना तट के दौरान नष्ट किया गया था। तब 2 मई 1982 को एच.एम.एस. डैस्ट्रॉयर ने ''जनरल बैलग्रेड'' नामक युद्धपोत को डुबा दिया था।

मॉस्कोवा में 510 क्रू मैम्बर थे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यूक्रेन की ''एंटी शिप'' मिसाइल ''नैप्च्यून'' ने इस भारी भरकम जहाज को मार गिराया। अब तक नैप्च्यून मिसाइल को इतना शक्तिशाली नहीं माना जाता था कि, ''मॉस्कोवा'' जैसे बहु सुरक्षित जहाज को हानि पहुंचा सकता है।
- समुद्र तट से चलायी गयी ''नैप्च्यून मिसाइल'' की इस कामयाबी ने समुद्री युद्ध के सिद्धांतों में तब्दीली लाने के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है विश्व को।
- पर, गंभीर बात यह है कि, इस समुद्री शिकस्त की खबर ने पुतिन को और हताश कर दिया है तथा वे कीव पर और भारी जवाबी आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं।
- अमेरिका ने ''साऊथ चायना सी'' में अपने भारी भरकम जलपोतों को समुद्र से दूर ले जाना शुरू कर दिया है, तट से चलायी जा रही मिसाइल से बचाने के लिये। चीन अमेरिका की इस मनःस्थिति का लाभ लेकर और आक्रमक ढंग से सक्रिय हो गया है, ''साऊथ चायना सी'' में।

'पहले युद्ध को बढ़ाओ और फिर बाद में घटाओ'

सी.आई.ए. के निदेशक विलियम बर्न्स, जो रूस में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं, ने रूस की इस ''शुद्ध नीति'' की गहरायी से व्याख्या की

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। यह एक तनावपूर्ण सर्वेक्षण है। रूस द्वारा परमाणु हथियारों का उपयोग किए जाने की आशंका वास्तविकता की ओर बढ़ती जा रही है। वह इस तरह के विध्वंसक हथियारों से पूरी तरह लैस है। इस खतरे की आशंका किसी ओर ने नहीं बल्कि अमेरिकी इन्टेलीजैंस के प्रमुख, सी.आई.ए. निदेशक विलियम बर्न्स ने व्यक्त की है। अमेरिका के अटलांटा में एक भाषण के दौरान बर्न्स ने कहा कि यूक्रेन आक्रमण में रूस को मिली नाकामयाबी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सामरिक या हल्के परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के लिए उकसा सकती है। रूस के पास कई परमाणु हथियार हैं, लेकिन उनकी मारक क्षमता अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में डाले गए परमाणु बम से कम है।

ए.एफ.पी. की एक रिपोर्ट के अनुसार बर्न्स ने कहा कि ''राष्ट्रपति पुतिन और रूस के नेतृत्व की अत्यधिक निराशा तथा सैन्य रूप से उन्होंने जो नाकामयाबी झेली है, उसे देखते हुए हम में से कोई भी सामरिक परमाणु हथियारों या कम क्षमता के संभावित प्रयोग के खतरे को हल्के में नहीं ले सकता।

जॉर्जिया टैक युनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए बर्न्स ने आगे बताया कि क्रेमलिन ने कहा था कि 24 फरवरी को आक्रमण शुरू होने के बाद ही उसने रूस की परमाणु शक्तियों को हाई अलर्ट पर कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने उसकी व्यावहारिक तैनाती की बहुत सी वास्तविक साक्ष्य नहीं देखी है, जो अधिक चिन्ताजनक है।

बर्न्स ने कहा कि ''स्पष्ट रूप से हम बहुत चिन्तित है। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति बाइडन तीसरा विश्व युद्ध, जो कि दहलीज पर है, को टालने के लिए अत्यधिक फिक्रमंद है। आप जानते हैं इसमें परमाणु संघर्ष संभव बन जाता है। रूस के पास कई सामरिक परमाणु हथियार हैं, लेकिन वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में डाले गये बम से कम सशक्त हैं। यदि पश्चिमी देशों के साथ परम्परागत लड़ाई में रूस की स्थिति थोड़ी खराब होती है तो ऐसी सूरत में वहां की सेना का एक सिद्धांत है जिसे ''एस्कलेट टू डिएस्कलेट'' कहा जाता है। इसके तहत अपनी स्थिति फिर से मजबूत करने के लिए शुरूआत में कम क्षमता वाले परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस परिकल्पना में इस संघर्ष में नाटो यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप करेगा। वह कोई आपात स्थिति नहीं होगी क्योंकि राष्ट्रपति बाइडन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह संभव है।''

यह स्मरण करते हुए कि वे कभी रूस में अमेरिका के राजदूत रहे थे, बर्न्स ने पुतिन के लिए बहुत रूखे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया, जो स्वयं को कर्मों की सजा देने वाला ईश्वरीय दूत मानता है और जो पिछले कई वर्षों से शिकायत, महत्वाकांक्षा और असुरक्षा के साथ दहक रहा है। बर्न्स ने कहा कि ''पुतिन प्रतिदिन यह दर्शाते हैं कि पतनोन्मुख शक्तियां भी उतनी ही हानिकारक हो सकती हैं, जितनी की उदित हो रही शक्तियां।

एक बात स्थिति को और उत्तेजक कर सकती है। वह है पश्चिमी मीडिया की खबरें कि पुतिन मानसिक रूप से अस्थिर हैं।

गुप्तचर सूत्रों से प्राप्त खबरें कहती हैं कि पुतिन कैंसर का स्टीरॉयड ट्रीटमैंट लेने के बाद शायद डिमेन्शिया, पार्किन्सन या उग्र व्यवहार के किस ब्रेन डिसआर्डर से पीड़ित हैं।

डेली मेल की एक खबर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूज़ीलैण्ड, यू.के. और यू.एस. को मिलाकर बने फाइव आईज़ इन्टैलीजेंस अलायंस के वरिष्ठ लोगों ने क्रेमलिन के निकट सूत्रों का हवाला देते हुए माना है कि यूक्रेन पर हमला करने वाले पुतिन के वैश्विक रूप से निंदनीय निर्णय के पीछे एक मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण है।

इन्टैलीजेंस समुदाय 69 वर्षीय पुतिन के बढ़ते अस्थिर व्यवहार के बारे में कई खबरें साझा कर रहा है। इनमें हाल ही प्राप्त फुटेज शामिल है, जिसमें वे मोटे दिखाई दे रहे हैं और क्रेमलिन के आगन्तुकों से बिना वजह दूरी बनाने पर जोर दे रहे हैं।

एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि ''कोई मानवीय स्त्रोत्र ही पुतिन की मनोस्थिति की सही तस्वीर पेश कर सकता है।'' पिछले पांच वर्ष का उससे अधिक समय से उनकी निर्णय क्षमता में विलक्षण बदलाव होते रहे हैं। पुतिन क्या कहते हैं और अपने आस पास की दुनिया को किस अंदाज से देखते हैं, उसे लेकर उनके आस पास के लोगों को उनमें एक यक़ीनी बदलाव नज़र आता है।''

- इस युद्ध नीति के तहत, बर्न्स के अनुसार, रूस अगर जमीनी युद्ध पर हारने लगा तो, कम शक्ति वाले ''न्यूक्लियर बम'' का विस्फोट कर सकता है।

इंगलैण्ड के शरणार्थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक योजना की घोषणा करते हुये कहा है कि कुछ शरणार्थियों को पुनर्वास के लिये हजारों मील दूर स्थित रवांडा भेजा जायेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, दक्षिणपंथी ग्रुपों तथा विपक्षी नेताओं ने इस घोषणा की तत्काल भर्त्सना की है।

रवांडा, जिसके मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को लेकर ब्रिटेन सहित कई देशों ने कड़ी आलोचना की है, ने कहा है कि इस संबंध में हुये एक समझौते के एक हिस्से के अन्तर्गत, उसे करीब 15.70

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इंगलैण्ड इन शरणार्थियों को, इंगलैण्ड में प्रश्रय देने के बजाय, उन्हें रवांडा भेजेगा तथा उनके पुनर्वास के लिये 157 मिलियन डॉलर भी देगा।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में दरारें दिखने लगीं

मोदी के तीन बार टोकने व चुप होने का आदेश देने पर कुद्ध हुए गडकरी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। आग भड़क रही है और भाजपा के बड़े नेता एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं तथा आँखे तरेर रहे हैं।

एक कैबिनेट मीटिंग में, जब कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को वह नहीं बोलने दिया गया, जो वे बोलना चाह रहे थे तथा तीसरी बार बोलने की कोशिश करने पर, प्रधानमंत्री ने उन्हें खामोश रहने के लिये कह दिया तो गडकरी अपनी सहजता खो बैठे।

उन्होंने कहा कि अगर मंत्री कैबिनेट मीटिंग में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते तो फिर वे अपने विचार कहाँ रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे यह सब पिछले आठ सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं लेकिन अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है।

गडकरी ने कहा कि उनके साथ 252 सांसद हैं लेकिन वे भाजपा संगठन के हित का खयाल करते हुये, चुपचाप बैठे हुए हैं।

यह खबर नागपुर से प्रकाशित समाचार पत्र ''लोकमत'' के एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रस्तुत की है। इस अखबार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- गडकरी ने झल्ला कर कहा कि, अगर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में अपनी बात नहीं कह सकते, तो कहां कहेंगे।
- यह खबर नागपुर से छप रहे अखबार लोकमत में छपी तथा गडकरी ने इस बात की पुष्टि की कि, यह खबर सच है।
- लोकमत मैनेजमैंट ने पी.एम.ओ. के कहने पर उस पत्रकार को बर्खास्त कर दिया, जिसने यह खबर भेजी थी।

मेयर सौम्या गुर्जर

जयपुर, 15 अप्रैल (का.सं.)। ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा डालने सहित आपराधिक षडयंत्र मामले में ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की व तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की रिवीज़न याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। वहीं इसी मामले में आरोपी चारों पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन ने उन पर आरोप तय करने वाले फैसले को चुनौती देते हुए रिवीज़न याचिकाएं दायर की थीं, इन पर भी शनिवार को ही सुनवाई होगी।

- ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के साथ अभद्रता करने के मामले में मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी।

रिवीज़न याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है। वहीं पार्षदों की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुस्लिम नेता अखिलेश से दूरी बनाने लगे हैं!

इन खफा नेताओं की शिकायत है कि, अखिलेश अब मुसलमानों पर हो रहे दुर्व्यवहार व भ्रष्टाचार के मामले उठाने में रूचि नहीं ले रहे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। मुस्लिमों से संबंधित मुद्दों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथित खामोशी को लेकर पार्टी में चौड़ी होती हुई दरार आज उस समय खुलकर सामने आ गई, जब पार्टी के एक नेता मोहम्मद कासिम रहीम ने आज लखनऊ में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।

जहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नजदीकी नेताओं ने मुस्लिम मुद्दों पर उनके रूख को एक ''रणनीति'' बताया, जो भाजपा की ''धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति'' तथा ओ.बी.सी. एवं ऊँची जाति के मतदाताओं को उसकी तरफ जाने से रोकने के लिये चुनावों से पहले अपनाई गई थी, वहीं अन्य नेताओं का कहना है कि यह रणनीति चुनावों में कोई फायदा पहुँचाने में विफल रही तथा इसलिये इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार की कथित घटनाओं पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की खामोशी पर सवाल खड़े करने वाले मुस्लिम नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

सपा के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम नेता ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, ''मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में रामनवमी-उत्सवों के दौरान, मस्जिदों पर भगवा बिग्रेड द्वारा किये गये हमलों तथा मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ रही हिंसक घटनाएं भी हमारे नेता की आत्मा झकझोर नहीं पा रही हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश जी चुनावी रणनीति के नाम पर चुप्पी नहीं साध सकते।

कासिम ने अपना इस्तीफा देते हुये कहा कि राज्य में मुस्लिमों पर किये गये कथित अत्याचारों के खिलाफ पार्टी प्रमुख तथा अन्य नेताओं ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने सपा प्रमुख पर आरोप लगाते हुये कहा कि मुस्लिमों से संबंधित मुद्दों को उठाने में उनकी कोई रूचि नहीं है।

आज़म खान, नाहीद हसन तथा शाहज़िल इस्लाम जैसे पार्टी विधायकों तथा अन्य मुस्लिम नेताओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुये, रईन ने मीडिया को जारी कर दिये पत्र में लिखा है: ''मुस्लिमों के प्रति सपा अध्यक्ष के ऐसे रवैये से अप्रसन्न होकर, मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। कासिम सुल्तानपुर जिले के सपा के क्षेत्रीय प्रभारी थे।

राजनैतिक पंडितों का मानना है कि सपा के मुस्लिम नेताओं में बढ़ते जा रहे असंतोष के परिणामस्वरूप, पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय को प्रसन्न एवं संतुष्ट रखना मुश्किल हो सकता है।

उनके अनुसार, अगर असंतोष बढ़ता है तथा जोर पकड़ता है तो सपा को 2024 में अल्पसंख्यक वोट बैंक को अक्षुण्ण बनाये रखने में तथा उतना अधिक समर्थन मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जितना उसे अभी-अभी समाप्त हुये विधानसभा चुनावों में मिला था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अखिलेश समर्थक इन खफा नेताओं को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि, यू.पी. चुनाव में भाजपा के खिलाफ ओ.बी.सी. व सवर्ण जातियों को अपने साथ लेने की रणनीति के तहत अखिलेश, मुस्लिमों के मुद्दों पर चुप्पी बनाये हुए थे।
- मुस्लिम वोट बैंक, सपा के पिछले इतिहास के कारण लगभग पूर्णतः सपा के समर्थन में आया।
- पर, फिर भी सपा केवल 111 सीटें ही जीत पायी, भाजपा की 273 सीटों पर विजय के सामने।
- एक पार्टी के पक्ष में पूर्ण रूप से संगठित होने की रणनीति फेल होने के कारण मुस्लिम नेताओं की यह रणनीति संभवतया बदलेगी।
- इसका लाभ कांग्रेस व बसपा को मिल सकता है, लोकसभा चुनाव में।

सोनिया को कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता कार्ड

नई दिल्ली, 15 अप्रेल (वार्ता)। कांग्रेस ने अपने डिजिटल सदस्यता कार्ड अभियान के तहत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को शुक्रवार को डिजिटल कार्ड उपलब्ध कराया।

पार्टी ने डिजिटल सदस्यता अभियान एक नवंबर 2021 को आरंभ किया था और इसके तहत पहला पंजीकृत डिजिटल कार्ड पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया गया था। पार्टी ने इस अभियान के अंत में आज सोनिया गांधी को सदस्यता डिजिटल कार्ड सौंपा।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि डिजिटल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पार्टी ने गत वर्ष एक नवम्बर को डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया था तथा पहला पंजीकृत डिजिटल कार्ड राहुल गांधी को दिया गया था।